



भारत की नई शिक्षा नीति के ,उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं एवं स्ट्रीम्स : एक विवेचना

डॉ. रमेश चन्दर, असिस्टेंट प्रोफेसर कस्तूरी राम कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन नरेला नई दिल्ली

सार : नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्कूलों तथा कॉलेजों में होने वाली शिक्षा की नीति तैयार की जाती है और भारत सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति का शुभारंभ कर दिया गया है । सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति में बहुत सारे अहम बदलाव किए गए हैं । नई एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव करने का प्रमुख कारण भारत को वैश्विक नजर में महाशक्ति बनाना है ।

भारत की नई शिक्षा नीति के तहत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GIR के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा का सर्वभौमिकरण किया जाएगा , नई शिक्षा नीति के आने से पहले 10+2 पैटर्न फॉलो किया जाता था परंतु इस नई शिक्षा नीति (NEP) के आ जाने से 5+3+3+4 के पैटर्न को फॉलो किया जाएगा ।

मुख्य शब्द : नई शिक्षा नीति, NEP

परिचय :

नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य भारत में अब तक जो शिक्षा प्रदान की जा रही है उस में क्रांतिकारी बदलाव लाना साथ ही भारत के शिक्षा को वैश्विक स्तर पर खड़ा करना है । जैसे हमारे भारत का इतिहास है कि पूरी दुनिया भारत से हमेशा सीखते आ रही हैं वैसे ही भारत को ज्ञान के क्षेत्र में महाशक्ति बनाना भी नई शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है ।

नई शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा का सर्वभौमिकरण किया जाएगा साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत सरकार के माध्यम से पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे संशोधन किए गए और कुछ नई सुविधा को भी जोड़ा गया है ।

भारत की नई शिक्षा नीति से शिक्षा में गुणवत्ता के साथ सुधार भी आएंगे जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो पाएगी ।

नई शिक्षा नीति की विशेषताएं

- भारत की नई शिक्षा नीति के आ जाने से मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा ।
- नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाएगा जिसके तहत Medical और Law की पढ़ाई को शामिल नहीं की गई है ।
- भारत में पहले की शिक्षा नीति के तहत 10+2 पैटर्न को फॉलो किया जाता था परंतु अब इस नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 5+3+3+4 के पैटर्न को फॉलो किया जाएगा जिसके तहत 12 साल की स्कूली शिक्षा दी जाएगी साथ ही 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा को भी शामिल किया गया है ।
- भारत की नई शिक्षा नीति के तहत स्टूडेंट को एक बड़ी राहत छठी कक्षा में मिलेगी क्योंकि छठी कक्षा से व्यवसायिक प्रशिक्षण , इंटरनशिप को भी आरंभ कर दिया जाएगा ।
- पांचवी कक्षा तक शिक्षा मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान की जाएगी :- यानी पांचवी कक्षा तक छात्र अपनी भाषा में ही पढ़ाई कर सकते हैं ।
- पहले जैसे साइंस , आर्ट्स तथा कॉमर्स के स्ट्रीम हुआ करते थे उसके तहत छात्रों को एक निश्चित विषय की पढ़ाई करनी होती थी लेकिन अब ऐसी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है ।



- उदाहरण से समझते हैं :- यदि कोई छात्र फिजिक्स का चयन करता है तो वह चाहे तो साथ में अकाउंट या आर्ट्स के भी सब्जेक्ट की पढाई नई शिक्षा नीति के तहत कर सकता है ।
- छात्रों को छठी कक्षा से ही कंप्यूटर और एप्लीकेशन के बारे में जानकारी दी जाएगी साथ ही उन्हें कोडिंग ही सिखाई जाएगी ।
- सभी स्कूलों को डिजिटल किया जाएगा
- सभी प्रकार के कंटेंट को क्षेत्रीय भाषा में ट्रांसलेट भी किया जाएगा ।
- नई शिक्षा नीति के तहत वर्चुअल लैब भी डेवलप किए जाएंगे ।

भारत की नई शिक्षा नीति के लाभ

- भारत में इस नई शिक्षा नीति को लागू करने का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत के छात्रों को सक्षम बनाना है ।
- नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए GDP का 6% हिस्सा केंद्र सरकार के द्वारा खर्च किया जाएगा ।
- पढाई में संस्कृत और भारत की जो प्राचीन भाषा है उनको अहम भूमिका दी जाएगी संस्कृत को IIT के क्षेत्र में भी आगे ले जाया जाएगा साथ ही जो छात्र चाहे संस्कृत भाषा में ही अन्य सब्जेक्ट की पढाई कर सकते हैं ।
- बोर्ड परीक्षा को भी बहुत आसान कर दिया जाएगा पहले जो छात्र सोचते थे कि बोर्ड परीक्षा के समय में ही केवल बोर्ड की तैयारी दो-तीन महीने में पढ कर कर ली जाए इस व्यवस्था को खत्म कर दी जाएगी अब छात्रों को साल भर पढाई करनी होगी और बोर्ड परीक्षा दो चरणों में ली जा सकेगी ।
- पढाई को आसान बनाने साथ ही छात्रों को समझ में आने योग्य बनाने के लिए पढाई क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल किया जाएगा ।
- हायर एजुकेशन लेवल पर एमफिल डिग्री को खत्म किया जा रहा है ।
- नई शिक्षा नीति के तहत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को मेन सिलेबस में रखा गया है ।
- नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को 3 भाषा सिखाई जाएंगे जो राज्य को अपने स्तर पर निर्धारित करना होगा ।
- नई शिक्षा नीति के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी ।
- भारत में नई शिक्षा नीति को निचले स्तर पर कार्य में लाने के लिए बहुत सारे संस्थान स्थापित किए जाएंगे जिससे New Education Policy (NEP) को सुचारू रूप से चलने में मदद मिल सकेगी ।
- इस नई शिक्षा नीति के आ जाने से बच्चों को कौशलपूर्ण बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा , साथ ही उन्हें पढाई भी विशेष रूप से कराई जाएगी ।
- भारत की नई शिक्षा नीति के आ जाने से स्टूडेंट के ऊपर से पढाई का बोझ कम होगा और उन्हें सीखने के क्षेत्र में काफी उन्नति प्रदान होगी । यानी अब विद्यार्थी रट्टा मार की जगह कौशलपूर्ण और योग्य बनेंगे ।

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के विभिन्न चरण

भारत की नई शिक्षा नीति विशेष रूप से चार चरणों में काम करेगी , 5+3+3+4 के पैटर्न को प्रयोग में लेकर स्टूडेंट की शिक्षा को आगे बढ़ाया जाएगा । इस नए पैटर्न के तहत 12 साल की स्कूली शिक्षा तथा 3 साल प्री



स्कूली शिक्षा शामिल है । New Education Policy 2022 को सरकारी तथा प्राइवेट स्कूल दोनों संस्थाओं के द्वारा फॉलो किया जाएगा ।

1. फाउंडेशन स्टेज :- फाउंडेशन स्टेज में 3 से 8 साल के बच्चे शामिल किए गए हैं , इस स्टेज में 3 साल की अपनी स्कूली शिक्षा तथा 2 साल प्री स्कूली शिक्षा जिसमें कक्षा 1 तथा दो शामिल है । फाउंडेशन स्टेज में छात्रों को भाषा कौशल और शिक्षण के विकास के बारे में सिखाया जाएगा और इस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा ।

2. प्रीप्रेटरी स्टेज :- प्रीप्रेटरी स्टेज के तहत 8 से लेकर 11 साल के बच्चे को शामिल किया गया है , प्रीप्रेटरी स्टेज के तहत कक्षा 3 से कक्षा पांच के बच्चे शामिल होंगे और इस स्टेज में बच्चों की भाषा और संख्यात्मक कौशल के विकास करण शिक्षकों का उद्देश्य रहेगा । प्रीप्रेटरी स्टेज तक बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा ।

3. मिडिल स्टेज :- मिडिल स्टेज के अंतर्गत कक्षा 6 से कक्षा 8 के बच्चे शामिल होंगे , मिडिल स्टेज के तहत कक्षा 6 के बच्चों को कोडिंग सिखाया जाएगा साथ ही उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण और इंटरनशिप भी प्रदान की जाएगी ।

4. सेकेंडरी स्टेज :- सेकेंडरी स्टेज के तहत कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के बच्चों को शामिल किया गया है , सेकेंडरी स्टेज के तहत जैसे बच्चे पहले साइंस, कॉमर्स तथा आर्ट्स लेते थे इस सुविधा को खत्म कर दी गई है , सेकेंडरी स्टेज के तहत बच्चे अपने पसंद की सब्जेक्ट ले सकेंगे और आगे की पढ़ाई कर सकेंगे ।

उदाहरण से समझे : यदि बच्चा साइंस के साथ कॉमर्स या फिर कॉमर्स के साथ आर्ट्स की पढ़ाई करना चाहता है तो इसकी भी अनुमति होगी ।

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 स्ट्रीम्स

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 के तहत छात्रों को सबसे बड़ी छूट स्ट्रीम को चयन करने में दिया गया है छात्र अगर चाहे तो साइंस स्ट्रीम का चयन कर आर्ट्स स्ट्रीम की भी पढ़ाई कर सकते हैं और आर्ट्स स्ट्रीम का चयन कर साइंस स्ट्रीम की भी पढ़ाई कर सकते हैं । नई शिक्षा नीति 2022 के तहत स्ट्रीम चुनने की प्रक्रिया को खत्म कर दी गई है । नई शिक्षा नीति के तहत प्रत्येक विषय को अतिरिक्त पाठ्यक्रम ना मान के पाठ्यक्रम के रूप में देखा जाएगा नई शिक्षा नीति के तहत खेल, नृत्य, मूर्ति कला ,संगीत इत्यादि को भी शामिल किया गया है ।

नई शिक्षा नीति 2022 के तहत एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार तैयार करेगी साथ ही शारीरिक शिक्षा को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा , वोकेशनल तथा एकेडमिक स्ट्रीम को अलग नहीं किया जाएगा जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों में दोनों क्षमताओं की विकास होने का अवसर प्रदान होगा ।

B.Ed अब 4 साल का

नई शिक्षा नीति 2022 के तहत B.ed को अब 4 साल का कर दिया गया है । 2030 के अंत तक शिक्षक की न्यूनतम योग्यता 4 साल की B.ed प्रोग्राम की होगी साथ ही सभी स्टैंडअलोन शिक्षण संस्था जो निर्धारित मानकों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ।

वोकेशनल स्टडीज पर फोकस करने की व्यवस्था



नई शिक्षा नीति के तहत वोकेशनल स्टडीज पर भी फोकस किया जाएगा अभी की स्थिति की बात की जाए तो हमारे देश में वोकेशनल स्टडीज सीखने वाले छात्रों की संख्या 5% से भी कम है । नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कक्षा छठी से कक्षा आठवीं तक के छात्रों को वोकेशनल स्टडीज सिखाने पर फोकस किया जाएगा ।

वोकेशनल स्टडीज में बागवानी ,लकड़ी का काम, मिट्टी के बर्तन, बिजली का काम इत्यादि से संबंधित जानकारी छात्रों को दी जाएगी । भारत की नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 2025 तक कम से कम 50% छात्रों को वोकेशनल स्टडीज पढ़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

मातृभाषा तथा क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा की व्यवस्था

जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था नई शिक्षा नीति के तहत पांचवी तक के छात्रों को मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने की व्यवस्था नई शिक्षा नीति के तहत की गई है । और यह सही भी रहेगा क्योंकि अगर छात्रों को उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाए तो वह बात को काफी आसानी से समझ पाएंगे । इसी बात को ध्यान रखते हुए National Education Policy 2022 के अंतर्गत पांचवी कक्षा तक के बच्चों को उनकी मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान करने की अनुमति दी गई है । (This language will be selected by the state government)

साथ ही क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा में पुस्तक भी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा यहां तक कि अगर पुस्तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध नहीं है तो शिक्षक और छात्र के बीच बातचीत का माध्यम क्षेत्रीय भाषा ही रहेगा । साथ ही कक्षा 1 से 2 के बच्चों को दो से 3 भाषाएं सिखाई जाएंगी।

नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षकों की भर्ती

National Education Policy 2022 के अंतर्गत यदि दी गई भाषाओं को बोलने वाले शिक्षकों की कमी पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में विशेष तौर पर प्रयास किए जाएंगे की दी गई भाषा बोलने वाले शिक्षक की भर्ती हो । अगर शिक्षकों की कमी पाई जाती है तो रिटायर हुए शिक्षकों को दोबारा से बुलाया जा सकता है ।

विदेशी भाषा सिखाने पर जोर

नई शिक्षा नीति के तहत माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को एक विशेष छूट देते हुए अपनी पसंदीदा भाषा सीखने का भी अवसर दिया जाएगा । यानी माध्यमिक विद्यालय के बच्चे अगर चाहे तो अपने पसंदीदा भाषा सीख सकते हैं , जिनमें फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश ,चाइनीस ,जैपनीज इत्यादि जैसी भाषाओं को शामिल किया गया है । इन सभी प्रयासों से भारत की शिक्षा नीति वैश्विक तौर पर उभर कर आएगी साथ ही भारत का जो पुराना इतिहास था वह फिर से दोहराया जा सकेगा ।

सन्दर्भ सूचि :

- <https://cscdigitalsevasolutions.com/new-education-policy-2022>
- <https://pmmodyojana.in/national-education-polic/>
- <https://www.techsingh123.com/new-national-education-policy/>
- <https://acrpro.org/new-education-policy/>
- <https://pmmodischeme.in/national-education-policy/>
- <https://www.sarkariyojnaa.com/new-education-policy-2/>



- <https://indiascheme.com/national-education-policy/>